

दैनिक रोकठोक लेखनी

R

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App



मनोज जरांगे ने रपत्म किया अनशन !

सरकार को दो महीने का दिया समय...

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 9 दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने सरकार से दो महीने के भीतर मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार के मत्रियों की तरफ से अनशन खत्म करने के लिए मनाने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक सभी मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक अपने घर में दाखिल नहीं होंगे।

जरांगे ने कहा कि अगर दो महीने में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन का बोनेतूत करेंगे। गुरुवार (2 नवंबर) को महाराष्ट्र के चार मत्रियों ने मनोज जरांगे से मुलाकात की। उनकी अपील पर जरांगे ने अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया। जालना में

मनोज जरांगे ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को समय देना चाहिए तो इस पर वहां मौजूद जनता ने 'हाँ' में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र भर के हमारे सब भाइयों को आरक्षण मिले, वे हमारी भूमिका है। इसलिए मैंने थोड़ा बक्स देने की सहमति दी है। इतने दिनों



से हमने इंतजार किया है। थोड़ा और भी करते हैं। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम रुकने वाले नहीं हैं।"

जरांगे ने कहा, "सरकार सीधे तौर पर सभी मराठों को कुनबी सर्टिफिकेट देने पर सहमत हुई है। मराठवाड़ा में 13 हजार कुनबी डिटेल्स मिली थी जिसके आधार पर आरक्षण देने की बात सरकार ने की

थी, जिसे हमने नकार दिया और अब सरकार सीधे तौर पर आरक्षण देने की बात मानी है।" गौरतलब है कि मराठा आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र में हिंसक हो गया था। कई नेताओं के घरों और दलों के दफतरों में आग लगा दी गई थी। पूरे राज्य में करीब 12 करोड़ का नुकसान हुआ। 160 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

दादर का प्राणी संग्रहालय से

चोरी हुए जानवर



सभी जानवर चोरी हो जाने का आरोप

मालिक ने बुधवार को शिवाजी पार्क मैदान के सामने बने निजी संग्रहालय से सभी विदेशी जानवर चोरी हो गए हैं। इस मामले में संग्रहालय की ओर से शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराया है। बता दें कि दो दिन पहले ही मनपा जी नॉर्थ वार्ड ने सोमवार को जिस प्राणी संग्रहालय हिस्से में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की थी। मरीन मॉर्च के नाम से चल रहे इस प्राणी संग्रहालय से पिछले दिनों एक मगरमच्छ का बच्चा मनपा के स्विमिंग पुल में मिला था। जिसको लेकर आरोप लगाया गया कि मगरमच्छ का बच्चा इसी प्राणी संग्रहालय से गया होगा। प्राणी संग्रहालय से दो दिन पूर्व सभी जानवर गायब हो जाने की शिकायत मिली जिसको लेकर संग्रहालय के

विवार में स्लैब गिरने से महिला की मौत !

विवार : विवार पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक घर का स्लैब गिरने से एक 34 वर्षीय महिला की मौत होने की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस ने सीआरपीसी कलम 174 के तहत केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार, शीतल शिवाजी पवार (34), मनवेल पाडा विवार पूर्व में रहती थी। 1 नवंबर को दादू प्लाजा, सी.एम.नगर, मनवेलपाडा विवार पूर्व स्थित मृतक (शीतल शिवाजी पवार) घर में सो रही थी, तभी घर के बैडरूम में छत का स्लैब उसके ऊपर गिर गया, आनन-फानन में उसे वसई विवार शहर महानगरपालिका जीवदानी देवी हॉस्पिटल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां सुबह 7,25 बजे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया। विवार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तथा शिकायतकर्ता (अमित सोलंकी) की शिकायत पर घटना में सीआरपीसी 174 के तहत दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

भिवंडी में 2 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज



भिवंडी : भिवंडी शहर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने दो झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाया है। नारपोली पुलिस ने इस मामले में भार्दीव की धारा 420, महाराष्ट्र प्रैक्टिसन एक्ट 1961 की धारा 33,36 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। किन्तु इस मामले में अभी दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पुलिस के मुताबिक भिवंडी महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शमीम अंसारी ने नारपोली पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराया है कि रामनगर साठेनगर आगे की जांच कर रही है।

विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी !

पांच राज्यों से पांच आरोपी गिरफ्तार



मुंबई : मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने भारत के अलग-अलग राज्यों से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वे आरोपी मजदूर वर्ग के लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ठगी किया करते थे। अब तक की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों ने करीब 300 लोगों को ठग कर करोड़ों रुपये कमाए हैं। इस मामले में रामकृपाल कुशवाहा को भिवंडी से गिरफ्तार किया गया है।

इसके अलावा रोहित सिंह को मुंबई, आशीष कुमार माहतो को दिल्ली, अमितोष गुप्ता को लखनऊ और राहुल कुमार चौधरी को

संपादकीय / लेख

फोन में सेंधमारी



फैसल शेख

(प्रधान संपादक)

अलर्ट 150 देशों में भी भेजा गया है, जहां एप्पल के आईफोन इस्तेमाल किए जाते हैं। साफ मायने हैं कि यह चेतावनी वैश्विक है, लिहाजा विपक्षी नेताओं की चीखा-चिल्ली महज सियासत है। एप्पल ने अपने बयान में यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि खुफिया संकेतों के आधार पर ऐसे अलर्ट आते हैं, जो अधूरे और गलत भी साबित हो सकते हैं। कंपनी ने सरकार द्वारा प्रायोजित हमलावरों की बात तो की है, लेकिन किसी ‘विशेष सरकार’ का खुलासा नहीं किया है। एप्पल ने हैकिंग के ऐसे खतरों से निपटने वाले सिस्टम से इंकार किया है। कंपनी यह भी नहीं बता सकती कि अलर्ट किन हालात में देना पड़ा, क्योंकि यह जानकारी देने से हैकर्स उससे बचने के रास्ते खोज सकते हैं। यानी स्पष्ट है कि फोन हैकर्स चीन, पाकिस्तान या किसी अन्य देश के भी हो सकते हैं। एप्पल ने एक ही समय, एक ही साथ, विपक्षी नेताओं और 150 देशों को यह चेतावनी-संदेश भेजा है, लिहाजा संदेहास्पद और सवालिया लगता है। यदि हैकिंग दुई है या की जा रही है, तो वह अलग-अलग स्थान पर, अलग-अलग समय में की जानी चाहिए। फिर भी मान सकते हैं कि मोदी सरकार ने विपक्ष के कुछ नेताओं और प्रवक्ताओं के फोन हैक कराए हैं, लेकिन 150 देशों और अराजनीतिक चेरों के फोन हैक कराने में सरकार के सरोकार क्या हो सकते हैं?

उनसे हासिल क्या होगा? भारत में 2 करोड़ से अधिक लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया भर में करीब 146 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। क्या ये सभी मोदी सरकार के निशाने पर हैं अथवा सभी को अलर्ट भेजा गया था? एप्पल को इस संदर्भ में तमाम स्पष्टीकरण देने चाहिए। बहरहाल केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणानुसार जांच शुरू कर दी गई है। एप्पल भी जांच के दायरे में होगी। एप्पल से कथित 'राज्य-प्रायोजित हमलों' पर वास्तविक और सटीक जानकारी मांगी गई है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सट्ट-इन) इसकी जांच कर तह तक जाने की कोशिश करेगी। मंत्री ने इसे भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश और भटकाने वाली विपक्ष की राजनीति करार दिया है। 'फोन में सेंधमारी' कोई नया मुद्दा नहीं है। किसी की निजता और गोपनीयता पर हमला भी नहीं है। इजरायल से खरीदे गए एजासूसी सॉफ्टवेयर की चर्चा एक बार फिर मुखर हो रही है। हालांकि सर्वोच्च अदालत की निगरानी में जो जांच कराई गई थी, उसमें कुछ भी ठोस सामने नहीं आया था। तब शीर्ष अदालत ने अपने-अपने फोन सरकार में जमा कराने का विकल्प भी दिया था, ताकि भीतरी जांच हो सके कि उसकी जासूसी कराई गई अथवा नहीं। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपना फोन जमा नहीं कराया था। आज फिर पुराने, अपरिपक्व बयान दोहराए जा रहे हैं। सवाल तो यह है कि फोन हैंकिंग के संदर्भ में अडाणी की भूमिका क्या हो सकती है? राहुल गांधी ने किसे 'तोता' कहा है? क्या कांग्रेस सरकारों के कार्यकालों में अडाणी व्यापार नहीं करते थे? क्या उन्हें ठेके नहीं दिए गए? देश को ऐसे सवाल कांग्रेस नेता से पूछने चाहिए। दरअसल जिनके फोन में सेंधमारी के आरोप उछले हैं, उनमें अधिकतर चेहरे राजनीतिक तौर पर अप्रासांगिक हैं अथवा आरोपित हैं।

 +91 99877 75650

 editor@rokthoklekhaninews.com

 Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

गृहविभाग कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल - सुप्रिया सुले

मुंबई : राकांपा की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया ताई सुले ने महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जालना में अमानवीय लाठीचार्ज की कथा गया। पुणे में भी कोयता गैंग सक्रिय है। राज्य में ड्रग माफिया का सामाज्य है। मराठा, धनगर, लिंगायत समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आज महाराष्ट्र जल रहा है। ऐसे में राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। गृहविभाग कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तत्काल गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा लें, ऐसी मांग सुप्रिया सुले ने की है। विधान भवन की सीढ़ियों पर शिवसेना (उद्घव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में राकांपा सांसद सुप्रिया ताई सुले भी उपस्थित थीं। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए विधायकों ने तुरंत एक दिवसीय सत्र बुलाने की मांग की है। इस मांग को लेकर शिवसेना (उद्घव बालासाहेब ठाकरे) विधायक नरेंद्र दराडे, विलास पोतनीस, प्रकाश फाटरेंकर और अजय चौधरी,



राकांपा की कार्यकारी अध्यक्ष सांसद सुप्रियतार्ड मुले, राष्ट्रीय महासचिव विधायक जीतेंद्र आव्हाड, राज्य उपाध्यक्ष शशिकांत शिंदे और रोहित पवार ने विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।

सांसद सुप्रियाताई ने कहा कि राज्य की वर्तमान स्थिति के लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं और सरकार ने आरक्षण के लिए ४० दिन का समय बताकर जर्गे पाटील के साथ धोखा किया है। सुप्रिया ताई ने कहा कि नवले ब्रिज के पास आगजनी की

**पिछले साल ४,६९,३९२
सड़क दुर्घटनाएं, १,६८,४९९
लोगों की जान चली गई...**



मुंबई : भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्र द्वारा पिछले वर्ष २०२२ के लिए जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनसे पता चलता है कि भारत में पिछले साल कुल ४,६१,३१२ सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन हादसों में १,६८,४९१ लोगों की जान चली गई, जबकि करीब ४.४५ लाख लोग घायल भी हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएं झ २०२२’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुर्घटनाओं की संख्या २०२१ की तुलना में लगभग १२ प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि मरने वालों की संख्या ९.४ प्रतिशत बढ़ गई है। २०२२ में घायल होने वाले लोगों की संख्या में १५.३ प्रतिशत का इजाफा हुआ। बता दें कि मंत्रालय इस रिपोर्ट को पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर तैयार करता है। सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चलाने से सबसे अधिक हादसे होते हैं और इसी में सबसे अधिक लोगों की मौत होती है। वर्ष २०२२ में हुई लगभग ७५ प्रतिशत दुर्घटनाओं का कारण तेज रफ्तार में वाहन चलाना ही है। सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों के पीछे गलत साइड ड्राइविंग भी सबसे बड़े कारणों में से एक है, जिसका योगदान लगभग छह प्रतिशत है। नशे में गाड़ी चलाना और गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल दो अन्य बड़े कारण हैं, जो भारत में चार प्रतिशत से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में योगदान करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सड़क सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के कारण भी पिछले साल भारत में लगभग ७०,००० लोग मरे गए। वाहन में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीटबेल्ट अनिवार्य होने के बावजूद, २०२२ में इसे न पहनने के कारण लगभग १७,००० लोगों की जान चली गई। यही नहीं हेलमेट न पहनने के कारण भी करीब ५०,००० से ज्यादा दोषिया वाहन चालकों की भी मौत हो गई।

**प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत
वृद्धि के लिए विधेयक में सुधार
चाहती है मनपा...**



मुंबई : महांगाई, बेरोजगारी और अन्य तमाम अस्विधाओं के अभाव में जी रहे मुंबईकरों पर अब मनपा टैक्स का बोझ बढ़ानेवाली है। मुंबई में प्रॉपटी टैक्स में अब वृद्धि करने की तैयारी मनपा ने दर्शाई है। प्रॉपटी टैक्स वसूली के मूल्यांकन में कानूनी जटिलताओं का हवाला देते हुए, मनपा प्रॉपटी टैक्स में १० प्रतिशत वृद्धि के लिए विधेयक में सुधार चाहती है। इसके लिए मनपा राज्य की सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। सूत्रों की मानें तो आगामी शीतकालीन सत्र में यह विधेयक लाया जा सकता है। यह विधेयक पारित होने के बाद मुंबईकरों को प्रॉपटी टैक्स १० प्रतिशत अतिरिक्त अदा करना होगा।

जिससे मुंबईकरों को खूब लाभ हुआ, लेकिन अब यह सरकार और मनपा प्रशासक मिलकर मुंबईकरों पर अतिरिक्त बोझ डालने पर जुटे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनपा के पूर्वव्यापी टैक्स मूल्यांकन में शामिल कानूनी जटिलताओं के कारण वित वर्ष २०२३-२४ के लिए संपत्ति कर बिलिंग में देरी हो रही है। एक अधिकारी ने कहा कि आगे की समस्या से बचने के लिए और प्रॉपटी टैक्स में वृद्धि के लिए विधेयक में सुधार की आवश्यकता है। विधेयक में सुधार के लिए मनपा जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। मनपा ने वर्ष २०१० में प्रॉपटी टैक्स

मनपा प्रशासन पिछले लगभग १० सालों से मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सत्ताधारी रही शिवसेना ने मनपा में प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि का विरोध किया और मुंबईकरों पर यह बोझ बढ़ने नहीं दिया। शिवसेना (उद्घव बालासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्घव ठाकरे ने मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया था। इनाम ही नहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए उद्घव ठाकरे ने मुंबई में ५०० वर्गफुट तक के फ्लैट को प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किया था,

नवी मुंबई में अधिक रिटर्न का झांसा देकर युवक से 1.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी...

पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

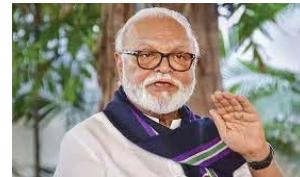


मुंबई : महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने 58 वर्षीय एक व्यक्ति को निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा कर लगभग 1.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नवी मुंबई पुलिस ने कहा कि आरोपी ने वाशी में रहने वाले एक शख्स को भरोसा दिलाया कि अगर वह उनके माध्यम से शेरों में निवेश करेगा तो उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। पुलिस अधिकारी ने कहा, इसके बाद आरोपियों ने लिंक मुहूर्या कराए और इस साल जुलाई से अक्टूबर के बीच शख्स से 1.37 करोड़

रुपये का भुगतान कराया। कई बार संपर्क करने के बाद भी जब उस व्यक्ति को पैसे नहीं मिले तो उसने पुलिस से संपर्क किया। नवी मुंबई पुलिस ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारी ने कहा कि पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में आरोपियों के नाम आर्यन भावर, आर्यन गुप्ता, एमा, ग्लोरिया और 'स्टॉक मार्केट एलायंस वीआईपी 991' के गुप्त एडमिन के रूप में हैं, उन्होंने बताया कि साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

किसानों ने धान की खरीद पर कठिनाइयों का हवाला दिया, भुजबल ने मदद का वादा किया

गोंदिया : महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में खरीफ सीजन 2023-24 के लिए सरकार द्वारा अनुमेदित केंद्रों पर कड़े नियमों और शर्तों के कारण धान की खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। किसानों और अन्य हितधारकों ने यहां जन प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छग्न भुजबल सहित कई निर्वाचित



नेताओं के साथ बुधवार को बैठक के दौरान दोनों जिलों के किसानों ने कहा कि उनके पास न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के अलावा कोई

विकल्प नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा अनुमेदित खरीद सुविधाएं अभी भी काम नहीं कर रही हैं। सरकार की ओर से धान लेने वाली कई सहकारी समितियों के सदस्यों ने खरीद केंद्रों के लिए कड़े नियम और शर्तों का मुद्दा भी उठाया। भुजबल ने हितधारकों को सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया तथा खरीद के नियमों और शर्तों में कुछ छूट देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए।

लोकल ट्रेन के ब्लॉक से मेट्रो की बल्ले-बल्ले, एक दिन में रिकॉर्ड 2.84 लाख यात्रियों ने किया सफर

मुंबई : लोकल ट्रेन की वेस्टर्न लाइन पर पिछले कुछ दिनों से ब्लॉक चल रहा है। ब्लॉक के चलते रोजाना करीब 200 ट्रेनें रद्द हो रही हैं। लोकल ट्रेन के ब्लॉक ने मुंबई की नई मेट्रो लाइन की बल्ले-बल्ले कर दी है। मंगलवार को मेट्रो-7 और मेट्रो-2 एकांडरों पर एक दिन में रिकॉर्ड यात्रियों ने सफर किया है। 31 अक्टूबर को 2.84 यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया। अप्रैल 2022 में मुंबई को मेट्रो 7 और 2 एक दिन में नई मेट्रो लाइन पर रुट पर लोकल ट्रेन की सुविधा नहीं है, अब वहां भी मेट्रो लाइन तैयार करने का काम सरकार कर रही है।



मरम्मत कार्य के कारण लोकल सेवा बाधित रही। ऐसे समय में मुंबई की नई मेट्रो लाइन ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता संबित कर दी है। अप्रैल 2022 में मुंबई को मेट्रो 7 और 2 एक दिन में नई मेट्रो लाइन पर रुट पर लोकल ट्रेन की सुविधा नहीं है, अब वहां भी मेट्रो लाइन तैयार करने का काम सरकार कर रही है।

किया है। इसमें से 1,87,8,963 यात्रियों ने बीते 9 दिनों में मेट्रो से सफर किया है। मेट्रो प्रशासन के अनुसार, मंगलवार को मेट्रो के आठ स्टेशनों को सर्वाधिक यात्रियों मिले हैं। मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वारा और टिकट काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतार नजर आई है। बता दें कि मुंबई की ट्रैफिक से बचने के लिए लोग लोकल ट्रेनों से सफर करना पसंद करते हैं। वहीं, जिन स्थानों पर लोकल ट्रेन की सुविधा नहीं है, अब वहां भी मेट्रो लाइन तैयार करने का काम

सरकार कर रही है।

महाराष्ट्र के धाराशिव में ग्रामीणों ने 'जेल भरो' प्रदर्शन शुरू किया

मुंबई : महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के कई गांवों के लोगों ने मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को 'जेल भरो' प्रदर्शन शुरू किया। राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर यहां आंदोलन कर रहे स्थानीय विद्यायक कैलास पाटील को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद जिले में 'जेल भरो' प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस अधिकारी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सैकड़ों मराठा कार्यकर्ता सुबह धाराशिव शहर और आनंदनगर ग्रामीण इलाके में एकत्र हुए। अधिकारियों ने बताया कि कौड़गांव में पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे से अपराह्न साढ़े 12 बजे तक करीब 100 कार्यकर्ताओं ने 'जेल भरो' प्रदर्शन में भाग लिया, जिनमें से 42 को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम



की धारा 68 के तहत हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा 25 अक्टूबर से जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में अनिश्चितकालीन अनशन फिर से शुरू किए जाने के कारण राज्य में प्रदर्शन तेज हो गया है। जरांगे ने इससे पहले अगस्त में भाग लिया, जिनमें से 42 को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम

मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर 29 अगस्त को प्रदर्शन शुरू किया था।

जरांगे ने उस समय 14 सितंबर को भूख हड्डाल समाप्त करते हुए सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए (24 अक्टूबर तक) 40 दिन का समय दिया था। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया था, जिसमें संबंधित अधिकारियों से मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कहा गया है ताकि उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ हासिल करने का मार्ग प्रस्तात हो सके। जरांगे ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि पूरे मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए।

ठाणे की चॉल में छत से भरभरकर गिरा प्लास्टर का टुकड़ा, महिला की मौत, 1 घायल



ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक चॉल के मकान की छत से प्लास्टर का एक टुकड़ा गिरने से 33 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और एक बुजुंग महिला घायल हो गई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। कलवा के सहायक नगर निगम आयुक्त सुबोध ठाणेकर ने बताया कि बृहस्पतिवार की मध्यावधि ठाणेकर के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ हासिल करने से क्रैकिट का टुकड़ा गिरने से चॉक्रिका कुंजूंग भारी रूप से घायल हो गई। नगर निगम के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ठाणे नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के समय चॉक्रिका के परिवार के चार सदस्य घर में थे।

शिक्षा विभाग के सचिव- अपर सचिव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने शिक्षकों के वेतन और बकाया भुगतान से संबंधित अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव और ऊपरी सचिव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण और न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के की खंडपीत ने बुधवार को चित्रा मेहर की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके आदेशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। मेहर के वकील आनंद परचोरे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए शिक्षकों को 'कुशल शिक्षकों' के वेतनमान के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। 2018 में, मेहर सहित कुछ शिक्षकों ने उपरोक्त वेतनमान के अनुसार वेतन के भुगतान की मांग करते हुए एचसी का रुख किया। 2022 में, उच्च न्यायालय ने सरकार को याचिकाकर्ताओं को 2.13 करोड़ रुपये और अन्य बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया। इसलिए शिक्षकों ने पिछले साल अवमानना याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सितंबर में कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव को एक नवंबर को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि इस बात का भी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है कि पहले के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारे पास महाराष्ट्र सरकार, स्कूल शिक्षा और खेल विभाग के सचिव रणजीत सिंह देयोल और महाराष्ट्र सरकार, स्कूल के अपर सचिव संतोष गायकवाड़ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टर्ट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टर्ट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं. 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई : 400016 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४, मदीना मैंशन, C११ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबांग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००९६, महाराष्ट्र मोबाइल नं. 998777 5650 फ्रांट्सप्प नं. 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com